

Daily Current Affairs

Date : 18 April, 2026

UTKARSH
CLASSES

CIVIL
SERVICES

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला - 2026
2.	मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना (MMMPY)
3.	भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट
4.	विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी (WADA)
5.	खासी और गारो भाषाएं
6.	शाहतोश ऊन
7.	ऑपरेशन नुमखोर
8.	बॉरोअर्स प्लेटफॉर्म
9.	नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज (NFLMW)
10.	भारत में भारत के चमगादड़ों की स्थिति (2024-25) रिपोर्ट
11.	AI गवर्नेंस और आर्थिक समूह (AIGEG)
12.	भारतीय अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता रिपोर्ट, 2025 (ISSAR 2025)
13.	विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO)

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला - 2026



चर्चा में क्यों?

- 17 अप्रैल, 2026 को सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने 'राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026' का उद्घाटन किया।

श्री नरेन्द्र मोदी
मन्त्रीय प्रधानमंत्री

मसालों की खुशबू से महकेगा जयपुर

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला - 2026

सहकार मसाले स्वाद एवं सुगन्ध में निराले, शुद्धता एवं विश्वास की कसौटी पर खरे

देश-प्रदेश के प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ मसालों की अनूठी प्रदर्शनी एवं बिक्री

अवधि: 17 से 26 अप्रैल तक | समय: प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक | स्थान: जवाहर कला केन्द्र, जेएलएन मार्ग, जयपुर

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

श्री गौतम कुमार दक
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)



मुख्य बिन्दु:

- आयोजन : 17 से 26 अप्रैल, 2026 तक।
- आयोजन स्थल : जवाहर कला केंद्र, जयपुर।
- आयोजक : सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉन्फेड)।
- शुरुआत : वर्ष 2003 से प्रति वर्ष।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

- वर्ष 2026 के मेले में 150 स्टॉल्स लगाई गई है।
- मेले में राजस्थान के साथ-साथ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, मध्य प्रदेश की सहकारी संस्थाएँ अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय कर रही हैं।

--2--

Daily Current Affairs

Date : 18 April, 2026



- **मेले में प्रदर्शित राजस्थान के प्रमुख उत्पाद :** मथानिया की लाल मिर्च, रामगंजमंडी एवं बारों का धनिया, नागौर का जीरा एवं कसूरी मैथी, जालोर की ईसबगोल, सिरोही की सौंफ, प्रतापगढ़ की हींग, चित्तौड़गढ़ की अजवाइन, पुष्कर का गुलकन्द, नाथद्वारा की ठण्डाई, भुसावर का अचार, राजसमंद का शरबत, सोजत की मेहंदी, डूंगरपुर का आम पापड़, झाड़ोल की अरहर दाल और बीकानेर के पापड़ आदि।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान में सहकारी आंदोलन:

- राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1904 में अजमेर से हुई।
- **वर्ष 1904 :** ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 'सहकारी ऋण समिति अधिनियम' पारित किया गया। तत्पश्चात् 25 अक्टूबर, 1905 को भिनाय (अजमेर) में राज्य की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई।
- **वर्ष 1904 :** डीग में राज्य के प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई।
- **वर्ष 1910 :** अजमेर में प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की शुरुआत।

सहकारिता से संबंधित राजस्थान के प्रमुख संस्थान:

संस्थान का नाम	स्थापना	मुख्यालय
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक)	1953	जयपुर
राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (राजफैड)	1957	जयपुर
राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ (तिलम संघ)	1990	जयपुर
राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान (RICEM)	1990	जयपुर
राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (RCDF)	1977	जयपुर
राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर (कॉनफेड)	1967	जयपुर
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड	1957	जयपुर

--:3:--

मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना (MMMPY)

चर्चा में क्यों?

- मातृ एवं बाल पोषण को सुदृढ़ बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना (MMMPY) एक महत्त्वपूर्ण पहल है।



मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना (MMMPY)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूसरी बार गर्भवती हुई महिला की स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार कर, जन्म के समय शिशुओं में कम वजन और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना है।

मुख्य बिन्दु:

- **क्रियान्वयन** : समेकित बाल विकास सेवा योजना (ICDS)
- **पूर्व नाम** : इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना।
- राजस्थान सरकार द्वारा संचालित यह एक नकद लाभ हस्तांतरण (DBT) आधारित योजना है।
- इस योजना के अंतर्गत 'दूसरी संतान की गर्भवती महिलाओं' एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को उनकी तथा शिशु की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

--:4::--

Daily Current Affairs

Date : 18 April, 2026



- योजना के अंतर्गत लड़की के जन्म पर ₹8,000 MMMPY + प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के माध्यम से एवं लड़के के जन्म पर ₹6,000 MMMPY के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (PMMVY)

- **शुरुआत :** केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2017 को केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना के रूप में।
- यह योजना महिला सशक्तीकरण से संबंधित भारत सरकार के 'मिशन शक्ति' का एक प्रमुख घटक है।
- **मंत्रालय :** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
- **प्रावधान :** योजना अंतर्गत प्रथम बार गर्भवती हुई महिला को दो किस्तों में ₹5000 तथा द्वितीय बार गर्भवती हुई महिला को केवल बालिका के जन्म एवं टीकाकरण पूर्ण करने पर ₹6000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

--:5:--



राष्ट्रीय परिदृश्य



भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट



चर्चा में क्यों?

- भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट गुजरात के धोलेरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में अधिसूचित किया गया।



मुख्य बिन्दु:

- AI-आधारित इस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन केंद्र का विकास टाटा सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना है।
- फैब्रिकेशन एक "फ्रंट-एंड" प्रक्रिया है जहाँ सिलिकॉन वेफर्स पर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए जाते हैं।

--6--

महत्त्व

- रणनीतिक आत्मनिर्भरता
- कौशल आधारित रोजगार का सृजन
- प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति
- **पूर्व की पहलें:** गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की ATMP (असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग) सुविधा और आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग (OSAT) इकाइयां शुरू की गईं।
- **लक्ष्य:** केंद्र सरकार का लक्ष्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के माध्यम से एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर प्रणाली स्थापित करना और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

SEZ मॉडल आधारित विकास ढांचा:

- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) किसी देश के भीतर ऐसे निर्धारित क्षेत्र होते हैं, जहाँ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अलग नियमावली और कर व्यवस्था लागू होती है।
- यह अधिसूचना 2025 में SEZ नियम, 2006 में किए गए महत्त्वपूर्ण संशोधनों के बाद आई है। इन संशोधनों का उद्देश्य निवेश बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना और कारोबार करना आसान बनाना है।
- **उदाहरण:** SEZ की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता 50 हेक्टेयर से घटाकर 10 हेक्टेयर कर दी गई, घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में शुल्क देकर SEZ में उत्पादित वस्तुओं को देश के भीतर बिक्री की अनुमति दी गई, आदि।

विश्व डोपिंग-रोधी एजेंसी (WADA)

चर्चा में क्यों?

- भारत ने WADA GAIIN अंतिम सम्मेलन में वैश्विक डोपिंग रोधी प्रयासों में सहयोग को सुदृढ़ किया है।



मुख्य बिन्दु:

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA):

- **स्थापना:** इसकी स्थापना 1999 में 'लॉज़ेन घोषणा' की शर्तों के अनुसरण में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई थी।
- **मुख्यालय:** मॉन्ट्रियल (कनाडा)
- **उद्देश्य:** डोपिंग मुक्त खेल के लिए एक सहयोगात्मक विश्वव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करना।
- **शासन:** WADA का शासन और वित्तपोषण खेल आंदोलन (स्पोर्ट मूवमेंट) और विश्व की सरकारों के बीच समान भागीदारी पर आधारित है।
- **प्रमुख पहलें:** ग्लोबल एंटी-डोपिंग इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क (GAIIN) पहल और विश्व डोपिंग रोधी कोड (Code)।

खासी और गारो भाषाएं

चर्चा में क्यों?

- मेघालय ने अंग्रेजी के अतिरिक्त देशज खासी और गारो भाषाओं को भी राज्य की राजकीय भाषा का दर्जा दिया है।

मुख्य बिन्दु:

- इन भाषाओं का उपयोग अब सरकारी संचार में किया जा सकता है।
- राज्य के अधिनियमों में संशोधन के बाद, विधायक विधानसभा सत्र के दौरान इन भाषाओं में चर्चा और बहस कर सकेंगे।

खासी और गारो भाषाओं के बारे में:

- **खासी:** मोन-खमेर परिवार की खासी शाखा की सदस्य, जो ऑस्ट्रो-एशियाई (Austroasiatic) परिवार का हिस्सा है।
- **गारो:** मेघालय के गारो हिल्स जिलों की सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक, जो चीनी-तिब्बती भाषा परिवार के बोडो समूहों में से एक से संबंधित है।
- **नोट:** दोनों भाषाएं वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं।

शाहतूश ऊन

चर्चा में क्यों?

- दिल्ली की एक अदालत ने जयपुर स्थित एक आर्ट गैलरी के मालिक को शाहतूश शॉल का अवैध रूप से निर्यात करने के प्रयास के लिए दोषी ठहराया है।

मुख्य बिन्दु:

- शाहतूश ऊन तिब्बती मृग (चिरू) के बालों से प्राप्त किया जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए इस जानवर को मारा जाता है।
- भारत में शाहतूश का व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसे विश्व स्तर पर भी प्रतिबंधित किया गया है।



तिब्बती मृग (पेंथोलॉप्स हॉजसोनी)

- चिरू एक मध्यम आकार का बोविड (पशु प्रजाति का पशु) है जो तिब्बती पठार (3,250-5,500 मीटर) के उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन स्टेपी क्षेत्रों में पाया जाता है।

--:10:--

Daily Current Affairs

Date : 18 April, 2026



- **निवास स्थान:** ये चीन के तिब्बत, किंघाई और शिनजियांग के शुष्क, ठंडे घास के मैदानों में निवास करते हैं, और भारत के लद्दाख (चांगथांग क्षेत्र) में इनकी एक छोटी आबादी पाई जाती है।
- **संरक्षण स्थिति:** इसे वर्तमान में आईयूसीएन रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
इसे सूचीबद्ध किया गया है:
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची प्रथम ,
- लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES) का परिशिष्ट I (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध) 1975 से लागू है।

UTKARSH

CIVIL SERVICES

-:11:-

ऑपरेशन नुमखोर



मुख्य बिन्दु:

- वाहन तस्करी और फर्जी पंजीकरण रैकेटों पर देशव्यापी कार्रवाई करने वाले ऑपरेशन नुमखोर पर आगामी भारत-भूटान संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक में चर्चा होने की संभावना है।

ऑपरेशन नुमखोर

- इसे सितंबर, 2025 में कोच्चि स्थित सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त कार्यालय द्वारा शुरू किया गया था।
- यह अभियान भूटान के रास्ते प्रीमियम सेकंड-हैंड वाहनों की तस्करी और जाली पंजीकरण दस्तावेजों के उपयोग को लक्षित करता है, जिसमें कथित तौर पर मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) के अधिकारी शामिल हैं।

आर्थिक घटनाक्रम

बॉरोअर्स प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, विकासशील देशों ने IMF-विश्व बैंक स्प्रिंग मीटिंग्स 2026 में पहली बार 'बॉरोअर्स प्लेटफॉर्म' शुरू किया।



मुख्य बिन्दु:

बॉरोअर्स प्लेटफॉर्म:

- उद्देश्य:** यह पीयर लर्निंग और ऋण प्रबंधन क्षमता निर्माण के लिए एक समर्पित मंच है। यह संप्रभु ऋण समझौतों में उधार लेने वालों की आवाज को मजबूत करने का कार्य करता है।
- यह ऋण पुनर्गठन मंच नहीं है।
- सदस्य:** 30 संस्थापक सदस्य (भारत सहित); अध्यक्ष- मिस्र।
- सचिवालय:** संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास (UNCTAD)।
- महत्त्व:** यह उन उधार-लेने वालों को एक औपचारिक समन्वय तंत्र प्रदान करता है जिनका विदेशी ऋण 2024 में 11.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
- संप्रभु ऋण समझौतों पर लंबे समय से ऋणदाता के नेतृत्व वाले तंत्रों का प्रभुत्व रहा है। पेरिस क्लब इसका एक प्रमुख उदाहरण है।

नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज (NFLMW)

चर्चा में क्यों?

- कारखाना श्रमिकों के बीच हालिया अशांति ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी स्तर यानी नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज को अंतिम रूप देने के प्रयासों में तेजी ला दी है।

मुख्य बिन्दु:

नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज:

- परिचय:** यह अवधारणा 1991 में पहली बार चर्चा में आई थी और श्री झीनाभाई दरजी की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (NCRL) की सिफारिशों से संबंधित है।
- इसे देशभर में न्यूनतम मजदूरी में असमानता को कम करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर पेश किया गया था। यह एक समान मजदूरी संरचना की दिशा में प्रयास है।
- वर्तमान में, मजदूरी संहिता (2019) केंद्र सरकार को फ्लोर वेज (अधिकार) निर्धारित करने का अधिकार देती है।
- इसलिए, समुचित सरकारों (केंद्र और राज्य) को कौशल, क्षेत्र, व्यवसाय या अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर इस स्तर से ऊपर न्यूनतम मजदूरी तय करनी चाहिए।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

भारत में भारत के चमगादड़ों की स्थिति (2024-25) रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- भारत में चमगादड़ों का पहला आकलन इनके समक्ष खतरों और डेटा संबंधी प्रमुख समस्याओं को रेखांकित करता है।



मुख्य बिन्दु:

- यह रिपोर्ट नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल आदि द्वारा तैयार की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- **प्रजातीय विविधता:** लगभग 135 चमगादड़ प्रजातियाँ दर्ज की गईं। इनमें से 16 प्रजातियाँ स्थानिक हैं।
- IUCN द्वारा सात प्रजातियों को शीटेंड (संकटापन्न) श्रेणियों के तहत सूचीबद्ध किया गया।
- **खतरे:** शहरीकरण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 का स्रोत होने का कलंक मुख्य खतरे हैं।

--:15:--

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⚡

AI गवर्नेंस और आर्थिक समूह (AIGEG)

📢 चर्चा में क्यों?

- भारत की राष्ट्रीय AI गवर्नेंस रणनीति का नेतृत्व करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'AI गवर्नेंस और आर्थिक समूह (AIGEG)' का गठन किया।

📌 मुख्य बिन्दु:

- इसके माध्यम से भारत के AI गवर्नेंस दिशानिर्देशों और आर्थिक समीक्षा में की गई सिफारिशों को औपचारिक रूप दिया गया है।
- दिशानिर्देशों ने AI गवर्नेंस के लिए "संपूर्ण-सरकार" (whole-of-government) दृष्टिकोण पर जोर दिया है।

AI गवर्नेंस और आर्थिक समूह (AIGEG)

- यह एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी निकाय है। यह AI गवर्नेंस पर नीति निर्माण और विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय के लिए भारत का केंद्रीय संस्थागत तंत्र होगा।

संरचना (10-सदस्यीय निकाय):

- **अध्यक्ष:** केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री
- **उपाध्यक्ष:** केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री
- **अन्य सदस्य:** नीति निर्माण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और आर्थिक मामलों से जुड़े हितधारक। उदाहरण के लिए: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA), नीति आयोग के CEO, आदि।

Daily Current Affairs

Date : 18 April, 2026



- **विशेषज्ञ सहायता:** एक प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति (TPEC) द्वारा, जो वैश्विक रुझानों, नए खतरों और विनियामक कमियों पर तकनीकी सलाह देगी।

भारत की AI गवर्नेंस रणनीति

- **नीति आयोग की 'राष्ट्रीय AI रणनीति (2018)'**: 'सभी के लिए AI' दृष्टिकोण, समावेशी विकास और इंडियाAI मिशन जैसी पहलों के माध्यम से AI प्रणाली के लोकतंत्रीकरण पर जोर देती है।
- **सात सिद्धांत या सूत्र:** विश्वास, जन-केंद्रितता, जिम्मेदार नवाचार, समानता, जवाबदेही, समझदारी और सुरक्षा, लचीलापन एवं संधारणीयता।
- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के साथ एकीकरण तथा AI गवर्नेंस समूह जैसे संस्थागत ढांचे का निर्माण।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:17:-



महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट



भारतीय अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता रिपोर्ट, 2025 (ISSAR 2025)



चर्चा में क्यों?

- 'भारतीय अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता रिपोर्ट' भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने जारी की है। यह अंतरिक्ष की वर्तमान स्थिति का वार्षिक मूल्यांकन है।



मुख्य बिन्दु:

- **रिकॉर्ड संख्या में प्रक्षेपण:** वर्ष 2025 में 328 प्रक्षेपित मिशनों में 315 सफल रहे। इनमें 4198 ज्ञात परिचालन योग्य उपग्रह स्थापित किए गए।
- **चंद्रमा के अन्वेषण में बढ़ती अभिरुचि:** 2025 में चार चंद्र मिशन प्रक्षेपित किए गए। ये सभी निजी संस्थाओं द्वारा प्रक्षेपित किए गए थे।
- **ब्लू घोस्ट मिशन 1 चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला निजी क्षेत्र का पहला अंतरिक्ष यान बना।**
- **अंतरिक्ष में उपग्रहों की अधिक संख्या और जोखिम:** उपग्रहों के निकट आने की लगभग 1,60,000 चेतावनियां जारी की गईं, जो विशेष रूप से पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में उपग्रहों की अधिक संख्या को दर्शाती हैं।

भारत के लिए अंतरिक्ष परिदृश्य (2025 के अंत तक)

- **अंतरिक्ष यान:** वर्ष 2025 के अंत तक भारत से कुल 144 अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किए गए जिनमें निजी ऑपरेटरों/शैक्षणिक संस्थानों के प्रक्षेपण भी शामिल हैं।
- श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित GSLV-F15/NVS-02 वास्तव में भारतीय अंतरिक्ष यान का 100वां प्रक्षेपण था।

Daily Current Affairs

Date : 18 April, 2026



- सरकार के स्वामित्व वाले परिचालित उपग्रहों की संख्या पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में 22 और भू-समकालिक कक्षा पृथ्वी कक्षा (GEO) में 31 थी।
- सक्रिय डीप स्पेस मिशन: चंद्रयान-2 ऑर्बिटर (CH20) और आदित्य-L1
- प्रमुख उपलब्धियाँ: SpaDeX मिशन; भारतीय अंतरिक्ष यात्री गुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा निजी Axiom 4 क्यू मिशन का नेतृत्व करते हुए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा।
अंतरिक्ष में उपग्रहों के सुचारू संचालन बनाए रखने के लिए इसरो के प्रयास
- मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन (DFSM) के लिए प्रतिबद्धता: अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों ने 2024 में घोषणा की कि वे वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन सुनिश्चित करेंगे।
- स्वदेशी प्रयास: स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रेकिंग और विश्लेषण नेटवर्क (NETRA), श्रीहरिकोटा में मल्टी-ऑब्जेक्ट्स ट्रेकिंग रडार (MOTR) की स्थापना; बेकर नन शिमेट टेलीस्कोप (BNST), जिसे वर्तमान में नैनीताल में नवीनीकृत किया जा रहा है।
- वैश्विक मंचों में भागीदारी: इनमें इंटर-एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, IAA स्पेस डेब्रिस कमेटी, आदि शामिल हैं।

--:19::--

विश्व आर्थिक आउटलुक (WEO)

चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी नवीनतम WEO रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के GDP संवृद्धि पूर्वानुमान को थोड़ा बढ़ाकर 6.5% कर दिया है।



मुख्य बिन्दु:

- वैश्विक संवृद्धि दर कम होकर 2026 में 3.1% और 2027 में 3.2% रहने का अनुमान है।
- भारत मौद्रिक (नॉमिनल) GDP के संदर्भ में विश्व की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं से बाहर होकर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रथम स्थान पर अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और यूके हैं।

WEO:

- यह निकट और मध्यम अवधि में विश्व अर्थव्यवस्था का विश्लेषण और अनुमान प्रस्तुत करता है।
- यह वर्ष में दो बार प्रकाशित होता है और इसके बीच में अपडेट जारी किए जाते हैं।
- **IMF द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्ट्स:** ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर।